(iii) Denial of property rights in land to the original inhabitants in Mirzapur district of U.P. due to amendment in Indian Forest Act.

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्प्रति देश के उन समस्त राज्यों में जिनमें वन क्षेत्र है, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के सन् 1980 में संशोधन होने के कारण विकट समस्या उत्पन्न हो गई है और वह यह कि वहां के मूल निवासियों को भूमि बन्दोबस्त की कार्यवाही में जहाँ एक ओर भौमिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, वहीं पर सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में विकास के कार्यों में भी अवरोधक उत्पन्न हो रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, जहां पर भूमि बन्दोबस्त की कार्यवाही सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वहां वर्ग 4 तथा वर्ग 10 व भूमि पर भौमिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है और बहुत से मूल निवासियों को उद्वासित भी किया जा रहा है। यहां तक कि उनके घर, कृषि की भूमि, बगीचे, बन्धी तथा कुयें आदि वन सीमा में किए जा रहे हैं और इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा चार से लेकर धारा बीस तक का प्रकाशन करके मूल निवासियों को भूमि के कब्जे से बेदखल किया जा रहा है, जिससे घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। तीन वर्षों में अब तक जितने विकास के कार्यक्रम, जैसे बन्दियों का निर्माण, नहरों का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण पर वन विभाग ने रोक लगा दिया है। परिणामस्वरूप सरकार की बहुत सी योजनायें बेकार हो रही हैं और यदि इनको कुछ वर्षों में शुरू भी किया जायेगा, तो तब तक उनकी लागत बढ़ चुकी होगी और जनता भी समय से विकास कार्यों के लाभ से वंचित हो चुकी होगी।

इसलिये केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि इस समस्या के निराकरण के लिये अविलम्ब कदम उठाए जायें।

(iv) Need for probe through C.B.I. to investigate into possible links between smugglers and workers of Ghazipur Opium Factory.

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों गाजीपुर में गार्फिया की स्मगलिंग के कई गिरोह पकड़े गये। दूसरे स्थानों पर भी ऐसे गिरोह पकड़े गये जिसका सम्बन्ध गाजीपुर से था। गाजीपुर में अफीम का एक कारखाना है, जहाँ गार्फिया बनाई जाती है। स्मगलिंग से इस अफीम के कारखाने का गहरा सम्बन्ध है। चूंकि इधर गाजीपुर की पुलिस काफी सक्रिय हो गई है, इसलिए स्मगलिंग के करने वाले पकड़ में आ गये हैं। वास्तविकता यह है कि स्मगलिंग का यह धंधा बहुत दिनों से चलता आ रहा है।

इन गिरोहों के पकड़े जाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनकी अफीम फैक्टरी में काम करने वाले कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से गहरी साँठ-गांठ हो सकती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस बात की सी बी आई से जांच कराए कि पकड़े गये स्मगलरों और अफीम के कारखाने में काम करने वालों से क्या सम्बन्ध है और ऐसी भी व्यवस्था करें कि अफीम के कारखाने से गार्फिया की स्मगलिंग बन्द हो सके।

(v) Retrenchment of workers connected with Badajamda Sector (Orissa). Due to M.M.T.C.'s refusal to purchase iron ore.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack) : 15,000 workers connected with the Iron ore mines of Badajamda sector in the districts of Keonjhar and Sundargarh, Orissa have been thrown out of employment in the last one year due to the refusal of the Mineral and Metal Trading Corporation to purchase ore from this area. In the current financial year, the situation has been further aggravated and another 25,000 workers are going to be retrenched following the decision taken by 38 mines owners in the above two districts to close down 49 mines managed by them. The decision of MMTC and the mine owners is detrimental not only to the mine owners workers but for the economy of the State. The State Government will lose only in Joda mining office jurisdiction, a minin revenue of 1 Crore 69 Lakhs. The tota

impact would be more than this if the Bonai and Gondhamadan areas are taken into consideration. The nation will lose a production worth two crores of rupees. In addition to this, sales tax and income-tax earned by the Government will also be lost.

Most of the workers engaged in the industry are adivasis having no other means for sustenance. Therefore, they will only add to the starving millions and will make the situation worse.

In view of this, I demand that the Government of India should immediately direct the MMTC to increase its iron ore procurement quota from these districts. All retrenched workers should be provided employment by expanding mining operation. Further retrenchment of workers should be stopped forthwith.

14.30 hrs.

(vi) Acquisition of agricultural land of tribal villages in Namkom Police Station, Ranchi (Bihar) for establishing a permanent firing range.

[SHRI R. S. SPARROW *in the Chair*]

SHRI N. E. HORO (Khunti) : About a dozen tribal villages of Namkom Police Station in the district of Ranchi, Bihar, are being vacated by the State Government of Bihar for establishing a permanent firing practising range for the Indian Army. Since the Second World War, these villages were from time to time vacated for firing practice by the Army. Tribals have always protested against this.

Now the entire land including agricultural lands falling within these villages are being permanently acquired for the purpose stated, which means that the tribals will lose once for all their lands and forests held with traditional rights under the Chotanagpur Tenancy Act. This has created a great resentment among the tribals of that area.

It may be known that those villages fall within the Scheduled Area for tribals under the Indian Constitution and the State Government have no right to encroch upon the tribal lands without the consent of the Tribes Advisory Council. Bihar and the Governor of the State,

I request that the Government of India intervene in this matter and advise the Bihar Government to desist from acquiring these tribal villages; else, there will be tribal uprising not in the Ranchi district alone but in the entire tribal belt of Chotanagpur and Santhal parganas.

(vii) Need to give Status of Scheduled castes to the Vimukta jatis.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, पूरे देश में विमुक्त जातियों की आबादी काफी संख्या में है। पंजाब एवं हरियाणा में विमुक्त जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखी हुंई है। पहले यह जातियां क्रिन्सीलट्राइब्स के रूप में मानी जाती थी, अनेक कमेटियों की सिफारिशों के बाद भी इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। हरियाणा एवं पंजाब के इन जातियों के लोग शुरू से ही जनजातियों में शामिल होने के लिए जोर डाल रहे है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इन लोगों के हक में अक्टूबर, 1982 में फैसला भी दिया है। ये लोग 25.7 83 से वोट क्लब पर अनशन पर बैठ है। अतः सरकार से मांग है कि इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करें।

(viii) Need to ban import of formic acid

SHRI M.M. LAWNCE (Idukki) : Sir there are only two indigenous units in India manufacturing formic acid, namely, the Kerala Acids and Chemicals and the Periyar Chemicals, having licensed capacity of 1200 tonnes and tonnes, respectively. Because of liberal import policy of the Government, the foreign manufacturers are dumping low-priced formic acid produced as a by-product in large scale synthetic plants in USA and West Germany. The Periyar Chemicals is on the verge of closing down on account of this. The State Government, therefore, requested the Government of India to ban import of formic acid. The Minister for Petroleum and Chemicals informed the State Government that the total demand for formic acid in the country, 2000 TPA, is in excess of the production of the